MATTERS RAISED WITH PERMISSION

Possible misuse of public data on 'Vahan' mobile application

SHRI MD. NADIMUL HAQUE (West Bengal): Sir, it has been reported that public data published by Government of India mobile application called the Vahan Application is being misused. There is a serious concern that this Transport Ministry Application which allow users to identify vehicle owners is being used by miscreants for targeted violence through ascertaining identity of vehicle owners. The Vahan Application makes all vehicle registration records across India publicly available. It allows people to look up the name of a car owner by simply using their vehicle registration number. Sir, such open access to citizen's personal data poses not only a huge privacy risk, but, may also lead to a potential risk to human life and private property. Sir, in March, 2019, the Ministry for Road, Transport and Highways rolled out the bulk data sharing policy under which it chose to make the vehicle registration database public. Sir, individual consent was not sought for this. It allowed organizations to pay an annual fee of ₹ 3 crores and research and education institutions ₹ 5 lakhs to access the databases. In July 2019, the databases were sold to about 87 private and 32 Government entities at a cost of ₹ 65 crores. Sir, in the absence of a personal data protection law to protect people's online privacy, such selling and misuse of data is deeply worrying.

I urge the Ministry to stop public as well as private access to the data on the portal. May I take this opportunity to urge you to protect all Members not only for our right to data privacy, but also to ask clarifications from a Minister after he delivers his speech? Sir, what happened yesterday ...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: No; it is not connected with this. This is not acceptable. Strictly, you have to go through the Zero Hour mention and then complete it to get some justice. Now, Shri Harnath Singh Yadav.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

Need for a law to curb the growing population of the country

श्री हरनाथ सिंह यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय सभापति जी, मैं आपके और सदन के माध्यम से जनसंख्या विस्फोट की अत्यंत भयावह स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

महोदय, जनसंख्या वृद्धि की अभूतपूर्व स्थिति के कारण से क्षेत्रफल और संसाधनों पर ऐसा दवाब बढ़ रहा है कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, अस्पतालों से लेकर सड़कों तक, राशन

की कतारों से लेकर रेलवे स्टेशन तक, बाजारों से लेकर न्यायालयों तक, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण हम बेरोजगारी, खाद्य समस्या, कुपोषण, आवास, निर्धनता, कृषि व ग्रामीण विकास में बाधा, पर्यावरण तथा जल संकट एवं मानवीय स्वभाव में निरंतर बढ़ते तनाव जैसी अभूतपूर्व परिस्थिति से जूझ रहे हैं।

महोदय, वर्ष 1951 में देश की आबादी 36,10,88,400 थी और 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी 121 करोड़ हो गई और 2025 तक एक अनुमान के अनुसार 150 करोड़ हो जाएगी। ऐसे में हमें पीने का जल भी नसीब नही होगा। वर्तमान में प्रति व्यक्ति जल की जो उपलब्धता है, वह 1,525 घन मीटर है, जो 2025 में घटकर मात्र 1,060 घन मीटर रह जाएगी।

महोदय, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री माल्थस ने कहा था कि जनसंख्या दुगुनी गति से अर्थात 1,2,4,8,6,32 के क्रम से बढ़ती है, लेकिन जीवन के संसाधन 1,2,3,4,5,6 की गति से बढ़ते हैं। अत: बढ़ती जनसंख्या की भयावह स्थिति को देखते हुए, हमें सभी प्रकार के राजनैतिक, धार्मिक, जातीय आदि मत-मतांतरों से ऊपर उठकर देश के वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य को गढ़ने के लिए अत्यधिक मजबूत और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की आवश्यकता है।

महोदय, कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें हम दो और हमारे दो का प्रावधान होना चाहिए। जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करे, उसको सरकार द्वारा दी जाने वाली समस्त सुविधाएं खत्म कर देनी चाहिए।

साथ ही इस कानून को तोड़ने वालों को ग्राम पंचायत, वार्ड से लेकर विधान सभा, लोक सभा आदि के समस्त चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। अत: मैं आपके और सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जनसंख्या वृद्धि को राष्ट्रीय आपदा मानकर सरकार को जनसंख्या नियंत्रण कानून अविलम्ब और इसी सत्र में बनाना चाहिए, धन्यवाद।

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I associate myself with the matter raised by the hon. Member.

श्री राम नारायण डूडी (राजस्थान): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. विकास महात्मे (महाराष्ट्र): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री विजय पाल सिंह तोमर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री शमशेर सिंह मन्हास (जम्मू-कश्मीर): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री सकलदीप राजभर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री समीर उरांव (झारखंड): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री संजय सेठ (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री जुगलसिंह माथुरजी लोखंडवाला (गुजरात): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डा. प्रभाकर कोरे (कर्नाटक): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

श्री रेवती रमन सिंह (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

लेफ्टीनेंट जनरल (डा.) डी.पी. वत्स (सेवानिवृत्त) (हरियाणा): महोदय, मैं भी माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

Need to restore pre-14th Finance Commission share pattern for Centrally Sponsored Schemes

SHRI PRASHANTA NANDA (Odisha): Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak. Sir, the increase of devolution of Central taxes from 32 per cent to 42 per cent, following the recommendations of the 14th Finance Commission, is a welcome step. But, the effect of increased devolution has been upset to a large extent by several policy decisions of the Union Government. These include delinking of eight